प्रेषक.

पी०के०पात्रो, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांकः २६ सितम्बर, 2014

विषयः जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-8) के अन्तर्गत रौलियाणा मोटर मार्ग से लोहागढ़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.15 है0 (पूर्व में 8.55 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेत् ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 667 / 1जी-3673(बागे०) दिनांक 09.09.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 8बी / यू०सी०पी० / 06 / 100 / 2012 / एफ.सी. / लखनऊ / 18 दिनांक 04. 09.2014 के कम में जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-8) के अन्तर्गत रौलियाणा मोटर मार्ग से लोहागढ़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन एवं 338 वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 14.30 हैo किलपारा सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2 (1) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 14.30 है0 किलपारा सिविल सोयम भूमि को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु इसे वन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित व नामान्तरित कर दिया गया है। इसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्दर संरक्षित वन घोषित किया जायेगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

(3) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर

यथोचित वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।

(4) यदि मा० उच्चतम् न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-F.C. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि उच्च स्तर से बढोत्तरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(5) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से

अनुपालन किया जायेगा।

(6) परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायंगी।

(7) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं मरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(9) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायंगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(10) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी

प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(11) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।

(12) आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

(13) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान भूसंरक्षण के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किये

(14) निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(15) वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(16) प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(17) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति

को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय (पी०के०पात्रो) अपर सचिव।

153 (1) / X-4-14 / 1-2(02) / 2014 तददिनांकित्। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक (वन संरक्षण) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,इन्दिरा भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

2. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ०आर० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।

3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

7. नोडल अधिकारी,(पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तराखण्ड ग्रामीण सङ्क विकास अभिकरण, देहरादून।

8. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को वेबसाईट पर अपलोडिंग हेत् प्रेषित। 10. गार्ड फार्डल।

आज्ञा से (श्याम सिंह) उप सचिव।